झारखंड उच्च न्यायालय, राँची
(लेटर्स पेटेंट अपील क्षेत्राधिकार)
एल.पी.ए.संख्या 566 / 2023

सच्चिदानंद सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष पिता;- स्वर्गीय राम नंदन सिंह, निवासी ग्राम खरखौल चैचरिया, थाना हैदरनगर, डाकघर- हैदरनगर, जिला पलामू, राज्य झारखंड।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड जिसका कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची
3. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) झारखंड , कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची
4. उप पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखंड, कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची
5. उप पुलिस महानिदेशक सह नियंत्रण अधिकारी, जे.ए.पी.टी.सी. पद्मा, डाकघर और थाना- पद्मा,जिला-हजारीबाग
6. पुलिस अधीक्षक, जेएपी प्रशिक्षण केंद्र, पद्मा, डाकघर और थाना- पद्मा, जिला हजारीबाग।
7. अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, विशेष शाखा, झारखंड, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला रांची

... उत्तरदाताओं

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

: श्री मणींद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जय प्रकाश, एएजी-आईए:

: सुश्री ओमिया अनुषा, एसी से एएजी-आईए

---

12 दिसंबर 2023

प्रति, श्री चंद्रशेखर, न्यायाधीश

अंतर्वर्ती आवेदन सं. 10923/2023

याचिकाकर्ता ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत यह अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है जिसमें वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर करने में 8 दिनों की देरी की माफी मांगी गई है।

2. इस अंतर्वर्ती आवेदन में दिए गए बयानों के मद्देनजर, इस अपील को दायर करने में 8 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

3. तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन सं.10923/2023 की अनुमति है।

एल. पी. ए. संख्या 566/2023

4. सच्चिदानंद सिंह जो रिट याचिकाकर्ता हैं, ने रिट याचिका (सेवा) संख्या 6024/2015 में पारित रिट कोर्ट के 19 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती दी है, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

5. संक्षेप में कहा गया है, याचिकाकर्ता जिसे 8 सितंबर 1981 को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, को विभागीय कार्यवाही संख्या 26/2003 के तहत

विभागीय जांच का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए कदाचार का आरोप यह था कि 8 नवंबर 2003 को उसे एक राइफल और 50 राउंड गोलियां मिलीं और राइफल में 5 गोलियां लोड करने के बाद उस स्थान पर गया जहां अन्य प्रशिक्षु अपनी राइफलें साफ कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने श्याम बहादुर थापा से राइफल पकड़ने का अनुरोध किया, जो एक प्रशिक्षु पुलिस भी थे। राइफल की सफाई के दौरान श्याम बहादुर थापा ने फुलथ्रू बैरल में डाला और फुलथ्रू को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच राइफल से गोली चली जो उनकी कमर पर लगी और खून बहने से चोट लग गई। श्याम बहादुर थापा को इलाज के लिए हजारीबाग के एक अस्पताल लाया गया और इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ 9 नवंबर 2003 को बरही (पद्मा) थाना वाद सं.216 /2003 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता को उपरोक्त आरोप पर एक चार्ज मेमो जारी किया गया था और जांच अधिकारी ने 6 सितंबर 2004 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह राय दी गई थी कि याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण राइफल से गोली चलाई गई थी जिससे श्याम बहादुर थापा की मौत हो गई थी। झारखंड सशस्त्र पुलिस (प्रशिक्षण केंद्र) पद्मा के पुलिस अधीक्षक ने जांच अधिकारी द्वारा दी गई राय को स्वीकार कर लिया और दो काले निशान के बराबर एक वार्षिक वेतन वृद्धि को जब्त करने की सजा सुनाई, जिसका भविष्य की वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, जैसा कि 17 नवंबर 2008 के आदेश से पता चलता है, पुलिस महानिदेशक ने सजा के आदेश की समीक्षा की और एक अस्थायी राय बनाई कि याचिकाकर्ता को दी गई एक वार्षिक वेतन वृद्धि की जब्ती की सजा पूरी तरह से अपर्याप्त थी और तदनुसार, 29 मई 2008 को उसे नोटिस जारी किया जिसमें उसे उक्त नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2008 के माध्यम से अपना बचाव करने के लिए एक महीने का समय मांगा, लेकिन उसने चार महीने बाद भी अपना

जवाब प्रस्तुत नहीं किया और इसलिए पुलिस महानिदेशक द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई, जिसे पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) ने 17 नवंबर 2008 के आदेश के तहत जारी किया था। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (सेवा) संख्या 2990/2009 में रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिका को 1 दिसंबर 2014 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक को 4 दिसंबर 2008 के उनके प्रतिनिधित्व का निपटान करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता के उक्त अभ्यावेदन को 23 नवंबर 2009 को खारिज कर दिया गया था, जिसे 17 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से उसे सूचित किया गया था। इस बीच, बरही (पद्मा) थाना वाद सं.216/2003 से उत्पन्न टीआर सं. 522/2007 के अनुरूप जी.आर वाद सं.2658/2003, 25 मई 2007 को दिए गए फैसले से याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया।

6. उक्त निर्णय में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, ने निम्नलिखित राय दी:

> "21. आइए देखें कि क्या कोई उतावलापन या लापरवाही जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक आवश्यकता है, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित की गई है। अभिलेख में केवल दो गवाह हैं, जिन्होंने घटना देखी है। वे पीडब्लू 1 और 2 हैं लेकिन पीडब्ल्यू 1 ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त की ओर से कोई उतावलापन या लापरवाही थी, हालांकि उसने अनुच्छेद 1 में कहा है कि एक व्यक्ति की राइफल को दूसरे व्यक्ति द्वारा साफ नहीं किया जाता है। इस सवाल पर बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई है लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई कानून पेश नहीं किया गया है। वास्तव में, यह एक प्रशिक्षण केन्द्र था और मृतक एक प्रशिक्षु था और अभियुक्त भी एक प्रशिक्षु था। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त की स्थिति एक लर्नर लाइसेंस होने की तरह होगी और एससी सीआर रूलिंग वॉल्यूम VI, पेज सं.377, सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कानून में ऐसी कोई पूर्वधारणा नहीं है कि कोई व्यक्ति, जिसके पास केवल लर्नर लाइसेंस है और जिसके पास बिल्कुल भी लाइसेंस

नहीं है, ड्राइविंग नहीं जानता है और साक्ष्य के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के अंतर्गत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में, आरोपी की ओर से उतावलेपन या लापरवाही के बारे में कोई बयान पीडब्लू 1 और 2 द्वारा जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। वास्तव में, अनुच्छेद 8 पीडब्ल्यू 1 में कहा गया है कि वह यह नहीं कह सकता कि मृतक ने आरोपी की पूरी राइफल खींची थी और गोली चलाई गई थी क्योंकि वह मौजूद नहीं था। इसी तरह, अनुच्छेद 7 पीडब्ल्यू 2 में कहा गया है कि वह यह कहने में असमर्थ है कि घटना के बाद पहुंचने पर गोली कैसे चली।

22. चर्चा किए गए तथ्यों और कानून के मद्देनजर, मैं पाता हूं और मानता हूं कि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए, उसे दोषी नहीं पाया जाता है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने का आदेश दिया जाता है। वह और उनके जमानतदार अपने-अपने जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त हो गए हैं।

7. पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित आदेश, जो पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा जारी किए जाते हैं, को रिट याचिका (सेवा) संख्या 6024/2015 दायर करके चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

8. रिट न्यायालय ने रिट याचिका (सेवा) संख्या 6024/2015 में पारित दिनांक 19 जुलाई 2023 के आदेश में निम्नानुसार आयोजित किया:

"8. बार के पार के पक्षों को सुनने और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि तत्काल रिट याचिका में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा आरोपों का दोषी ठहराया गया है। जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होकर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने दंड दिया है जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ा दिया गया है और याचिकाकर्ता को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता एक प्रशिक्षु था और परिवीक्षा अवधि में था। पुलिस बल के सदस्यों से अत्यंत अनुशासित होने की अपेक्षा की जाती है। याचिकाकर्ता के

अनुशासनहीनता व्यवहार और दृष्टिकोण के कारण, उसकी कार्रवाई से एक साथी सहयोगी की मृत्यु हो गई जो अपने आप में एक गंभीर मामला है। यह न्यायालय पुलिस महानिरीक्षक सह पुलिस महानिदेशक के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कृत्य के लिए बर्खास्तगी का अधिकार दिया गया है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है जो हस्तक्षेप के लिए कोई विशेष ध्यान या जगह नहीं देता है। जांच अधिकारी ने प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच की है और याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रक्रियात्मक कमी नहीं बताई गई है और इस तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होकर दंड दिया है और इसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया गया था और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, जिसे पुलिस मैनुअल के नियम 853-क के तहत ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है। याचिकाकर्ता एक अनुशासित बल से संबंधित है और उसे अत्यधिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।

10. बिहार राज्य बनाम फुलपरी कुमारी के मामले में, (2020) 2 एससीसी 130 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विभागीय जांच के अनुसार पारित आदेश में हस्तक्षेप केवल 'कोई सबूत नहीं' के मामले में हो सकता है।

भारत संघ बनाम पी. गुणशेखरन, (2015) 2 एससीसी 610 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

"12. अच्छी तरह से स्थापित स्थिति के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, यहां तक कि जांच अधिकारी के समक्ष सबूतों की भी सराहना की है। आरोप-I के निष्कर्ष को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय पहली अपील की दूसरी अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227

के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में उद्यम नहीं करेगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:

(क) जांच एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है;

(ख) जांच इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है;

(ग) कार्यवाहियों के संचालन में नैसगक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) प्राधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुण-दोष से भिन्न कुछ बातों पर विचार करके निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने से स्वयं को निशक्त कर लिया है; 5 एलपीए सं.566 ऑफ 2023

(s.) अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने की अनुमति दी है;

(च) निष्कर्ष, इसके बहुत चेहरे पर, इतनी पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था;

(छ) अनुशासनिक प्राधिकारी ग्राह्य और तात्विक साक्ष्य को स्वीकार करने में गलती से विफल रहा था;

(ज) अनुशासनिक प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रूप से अग्राह्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था जिससे निष्कर्ष प्रभावित हुआ था;

(झ) तथ्यों का निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन, उच्च न्यायालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(i) साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा;

(ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना, यदि वह विधि के अनुसार किया गया है;

(iii) साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच करना;

(iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता में जाना;

(v) हस्तक्षेप, यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।

(vi) तथ्य की त्रुटि को ठीक क रना
चाहे वह कितनी भी गंभीर प्रतीत हो;

(vii) दंड की आनुपातिकता में तब तक जाएं जब तक कि वह अपनी अंतरात्मा को झकझोर न दे।

11. याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है, इसलिए उसे बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के बाद सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। केवल आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल होने का अधिकार नहीं मिलता है।

12. 2021 (4) जेबीसीजे 588 में रिपोर्ट किए गए अशोक कुमार नोनिया बनाम मैसर्स बीसीसीएल और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि, "आपराधिक मामले में केवल बरी होना बर्खास्तगी के बाद बहाली का आधार नहीं हो सकता है"।

13. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरिंदर मोहन आर्य (2004) 6 एससीसी 713 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

"39. कुछ परिस्थितियों में, एक सिविल कोर्ट का निर्णय आपराधिक अदालत पर भी बाध्यकारी है, हालांकि, इसके विपरीत सच नहीं है। (देखें करम चंद गंगा प्रसाद बनाम भारत संघ26.) हालांकि, यह भी सच है कि आपराधिक मामले और सिविल मामले में सबूत का मानक अलग है।

40. हम देख सकते हैं कि कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में, इस न्यायालय ने कहा:

'35. चूंकि दोनों कार्यवाहियों अर्थात् विभागीय कार्यवाहियों और आपराधिक मामले में तथ्य और साक्ष्य बिना किसी अंतर के समान थे, इसलिए साक्ष्य के दृष्टिकोण और भार के आधार पर विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले के बीच आमतौर पर जो अंतर निकाला जाता है, वह तत्काल मामले पर लागू नहीं होगा।

41. हमें यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने एक कानून निर्धारित किया है कि ऐसी सभी परिस्थितियों में सिविल कोर्ट या आपराधिक अदालत का निर्णय अनुशासनात्मक अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा क्योंकि यह न्यायालय बड़ी संख्या में निर्णयों में बताता है कि यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए देखें कृष्णकाली टी एस्टेट बनाम अखिल भारतीय चाह मजदूर संघ और प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम एस मणि। इसलिए, प्रत्येक मामले पर अपने तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और अन्य के मामले में कहा था। (2013) 1 एससीसी 598 में रिपोर्ट किए गए बनाम एस समुथिराम के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है

24 "माननीय बरी" अभिव्यक्ति का अर्थ आरबीआई बनाम भोपाल सिंह पांचाल 6 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उस मामले में, इस न्यायालय ने 46 की अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानजनक बरी से निपटने वाले विनियमन 4(2023) के प्रभाव पर विचार किया है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि केवल बरी होने से किसी कर्मचारी को सेवा में बहाली का अधिकार नहीं मिलता है, बरी करना, यह माना गया था, सम्मानजनक होना चाहिए। अभिव्यक्ति "माननीय बरी", "दोष से बरी", "पूरी तरह से दोषमुक्त" आपराधिक प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं, जो न्यायिक घोषणाओं द्वारा गढ़े गए हैं। यह ठीक से परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। जब अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के सबूतों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया था।

26. जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, बहाली के लिए सेवा नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया जाता है, तो कर्मचारी को बहाली सहित

किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। कारण यह है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के लिए आवश्यक सबूत का मानक और अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से की गई जांच पूरी तरह से अलग है। किसी आपराधिक मामले में, अभियुक्त का दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है और यदि वह युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहता है तो अभियुक्त को निर्दोष मान लिया जाता है। यह स्थापित कानून है कि एक आपराधिक अदालत में अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का सख्त बोझ अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक नहीं है और संभावनाओं की प्रधानता पर्याप्त है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक व्यक्ति तकनीकी कारणों से बरी हो जाता है या अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों को छोड़ देता है क्योंकि कुछ अन्य गवाह मुकर गए थे, आदि। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाहों से इस आधार पर पूछताछ करने के लिए कदम नहीं उठाए कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी मुकर गए थे। इसलिए अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि वर्तमान मामले में, उत्तरदाता को आपराधिक न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था और यदि ऐसा है भी, तो वह बहाली का दावा करने का हकदार नहीं है क्योंकि तमिलनाडु सेवा नियम ऐसा प्रदान नहीं करते हैं।

27. हमारे सामने ऐसे मामले भी आए हैं जहां सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि आपराधिक मामला दर्ज होने पर किसी कर्मचारी को निलंबित रखा जा सकता है और फौजदारी न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर उसे बहाल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, बहाली स्वचालित है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सेवा नियमों में यह प्रावधान हो सकता है कि घरेलू जांच के बावजूद, यदि आपराधिक न्यायालय किसी कर्मचारी को सम्मानपूर्वक बरी कर देता है, तो उसे बहाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी कर्मचारी को सेवा में बहाल किया जाना है या नहीं, यह मुद्दा इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या सेवा नियमों में बहाली के लिए ऐसा कोई प्रावधान

है और अधिकार के मामले के रूप में नहीं। तमिलनाडु सेवा नियमों में ऐसे प्रावधान अनुपस्थित हैं।

14. जेटी 2004 (7) एससी 333 में रिपोर्ट किए गए कृष्णकाली टी एस्टेट बनाम अखिल भारतीय चाह मजदूर संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि:

"यह न्यायालय आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद कामगारों की सेवाओं की समाप्ति की वैधता से चिंतित था। इस मामले में एक जैसी स्थिति से निपटते हुए, जहां बरी होने का कारण आपराधिक अदालत के समक्ष सबूतों की कमी थी और श्रम न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सबूत उपलब्ध थे, इस अदालत की राय थी कि कैप्टन एम. पॉल एंथोनी के मामले में निर्णय (सुप्रा) श्रमिकों के बचाव में नहीं आ सकता है।

15. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम बीके मीणा के मामले में, जेटी (1996) 8 एससी 684 में रिपोर्ट किया, यह माना गया है कि

"एक आपराधिक अदालत द्वारा बरी करना एक नियोक्ता को नियमों और विनियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा। दो कार्यवाही, आपराधिक और विभागीय, पूरी तरह से अलग हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके अलग-अलग उद्देश्य हैं। कार्यवाही के अनुशासनात्मक में, सवाल यह है कि क्या उत्तरदाता ऐसे आचरण का दोषी है, जो उसे सेवा से हटाने या कम सजा के योग्य होगा, जैसा भी मामला हो, जबकि आपराधिक कार्यवाही में, सवाल यह है कि क्या पीसी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज अपराध स्थापित हैं, और यदि स्थापित किया जाता है, तो उस पर क्या सजा दी जानी चाहिए। सबूत का मानक, जांच का तरीका और दोनों मामलों में जांच और मुकदमे को नियंत्रित करने वाले नियम काफी विशिष्ट और अलग हैं।

16. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को सजा बढ़ाने के लिए नोटिस का जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने जवाब नहीं देने का विकल्प चुना, जिसका अर्थ है कि आदेश को स्वीकार कर लिया गया।

17. पूर्वोक्त तथ्यों के मद्देनजर और कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

18. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने प्रस्तुत किया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित और पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा 17 नवंबर 2008 के आदेश के माध्यम से जारी किया गया आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत वैधानिक प्रावधान पुलिस महानिदेशक को वर्तमान मामले में सजा के आदेश की स्वत: समीक्षा करने की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं और इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने 29 मई 2008 के नोटिस का जवाब नहीं दिया, पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित 17 नवंबर 2008 के आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना और अवैध माना जाना चाहिए।

10. झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 851, 852 और 853-ए जो वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार पढ़ें:

851.(क) नियम 828 में वणत मुख्य दंडों के मामलों को छोड़कर कोई अपील नहीं की जाएगी।

(ख) बर्खास्तगी, हटाने, कमी, पदोन्नति या आवधिक वेतनवृद्धि को रोकने, वेतन की हानि सहित निलंबन, किसी विशिष्ट पद या विशेष परिलब्धि से हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक मामले में निम्नानुसार एक अपील होगी -

अधीक्षक द्वारा उप महानिरीक्षक को पारित आदेश के विरुद्ध;

उप महानिरीक्षक द्वारा महानिरीक्षक को पारित एक मूल आदेश के खिलाफ;

महानिरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को पारित मूल आदेश के खिलाफ। (ग) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश नियम 853 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होंगे।

(घ) किसी उच्चतर प्राधिकारी (राज्य सरकार से भिन्न) की सहमति से पारित आदेश को ऐसे वरिष्ठ प्राधिकारी का मूल आदेश समझा जाएगा।

852. अपील में प्रक्रिया- (ए) अपील की याचिकाएं या किसी आदेश के संशोधन के लिए उस अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी जाती है, उस तारीख के छह महीने के भीतर, जिस पर अपील को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी को उन आदेशों के बारे में सूचित किया गया था जिनके खिलाफ वह अपील करता है:

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी अपने विवेक पर, दिखाए गए अच्छे कारण के लिए, अवधि को 12 महीने तक बढ़ाएं।

(ख) अपील की प्रत्येक याचिका या किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आरोपों, बचाव और आदेश की प्रमाणित प्रतियों के साथ अन्यथा इसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी याचिकाओं और अपीलों पर न्यायालय शुल्क की मुहर नहीं लगाई जानी चाहिए।

(ग) यह उस अधिकारी का कर्तव्य होगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है और जिसके कार्यालय में अपील याचिका का निपटारा किया गया है, कि सभी कागजात एक ही बार में वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिए जाते हैं, लेकिन उन मामलों में जिनमें अपील नहीं होती है, इन कागजात को अग्रेषित नहीं किया जाएगा और कारणों को अपील दायर करने वाले अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा। (घ) वह अधिकारी, जिसके समक्ष अपील फाइल की गई है, अपने कार्यालय में अपीलों से संबंधित एक पृथक रजिस्टर रखेगा। इसे पी.एम. फॉर्म सं.115 ए में रखा जाएगा। कार्यालय में फाइल प्राप्त होने से एक माह के भीतर अपील का निस्तारण किया जाए तथा आदेश की सूचना अपील दायर करने वाले अधिकारी को दी जाए।

(ङ) अपील रजिस्टर में (जो केवल उप महानिरीक्षक/महानिरीक्षक के कार्यालयों के लिए आवश्यक है) आदेशों के लिए प्राप्त अपील के अलावा, वे अपीलें जो केवल अग्रेषण के लिए प्राप्त हुई हैं, दर्ज नहीं की जाएंगी। आदेश के लिए प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन दर्ज किए जाएं। इन रजिस्टरों की समय-समय पर कार्यालय प्रमुखों द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि लंबित मामलों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।

(च) अपील दायर करते समय, आरोपित अधिकारी विशेष रूप से यह देखेगा कि अभ्यावेदन में कोई असंगत और असंगत तथ्य नहीं हैं और किसी विभागीय अधिकारी के विरुद्ध कोई आधारहीन आरोप नहीं लगाया गया है। यदि इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अलग से विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए

.....

853-ए. (ए) महानिरीक्षक किसी भी मामले में फाइल के लिए कॉल कर सकता है, भले ही कोई अपील झूठ न हो और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझ सकता है। उप महानिरीक्षक किसी भी फाइल के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आदेश के लिए अपनी सिफारिश के साथ इसे महानिरीक्षक को संदर्भित करना चाहिए। उपरोक्त कार्यवाही विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश की तारीख से उचित समय के भीतर की जानी चाहिए। (ख) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी अनुशासनिक मामले में कार्यवाही के लिए बुला सकती है, भले ही कोई अपील या स्मारक झूठ न हो, और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(ग) जब कोई अपील दायर की गई है और महानिरीक्षक अपना दिमाग लगाने पर सोचता है कि उसे सजा बढ़ानी चाहिए, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही उस आदेश में उल्लेख करना चाहिए कि नियम 853 ए (ए) में दी गई शक्तियों के अनुसार, उसने वृद्धि के लिए इसकी समीक्षा करने और कारण बताओ प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, आदि, जहां आवश्यक हो।

11. झारखंड पुलिस मैनुअल नियम 851 (ए) के तहत नियम 828 में उल्लिखित बड़ी सजा के मामलों में अपील प्रदान करता है। नियम 824 के तहत, (ए) बर्खास्तगी (बी) निष्कासन (सी) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (डी) रैंक में कमी (ई) अंतिम वेतन वृद्धि (ओं) या भविष्य की वेतन वृद्धि (ओं) की जब्ती और (एफ) काला निशान या निशान प्रमुख सजा है जो नियम 828 के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

12. पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दो काले निशानों के समतुल्य एक वेतनवृद्धि को रोकने के दिनांक 15 मई, 2006 के दंड आदेश की पुलिस महानिदेशक द्वारा समीक्षा की गई थी और नियम 853-क के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में वृद्धि की गई थी। याचिकाकर्ता को 28 दिसंबर 2006 को सजा बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया गया था और उसे सेवा से बर्खास्तगी की प्रस्तावित सजा का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री जय प्रकाश नियम 852 का उल्लेख करते हैं जिसमें अपील या पुनरीक्षण दायर करने के लिए छह महीने की अवधि का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद सजा बढ़ाने के लिए 29 मई 2008 को नोटिस जारी करने में पुलिस महानिदेशक द्वारा शक्तियों का प्रयोग नियम 853-ए के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। हालांकि, हम पाते हैं कि नियम 852 का परंतुक अपीलीय प्राधिकारी को दोषी पुलिस अधिकारी द्वारा दिखाए गए अच्छे कारण के लिए सीमा की अवधि को और छह महीने तक बढ़ाने का विवेकाधिकार देता है। यह एक स्थापित कानून है कि किसी कानून के तहत सट्टेबाजी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और ऐसे आदेश अनुचित और अवैध होंगे। झारखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर पुलिस महानिदेशक ने नियम 853-ए के तहत शक्तियों का सही प्रयोग किया, इस अनुमान पर आधारित है कि याचिकाकर्ता अपील दायर नहीं कर सकता था या अपीलीय प्राधिकारी देरी को माफ नहीं कर सकता था और सीमा की अवधि को और छह महीने तक बढ़ा सकता था, जैसा कि नियम 852 के परंतुक के तहत प्रदान किया गया है। इससे कोई संदेह नहीं है कि एक वैधानिक अपील को आम तौर पर इस आधार पर खारिज नहीं किया जाता है कि यह सीमा की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था और बहुत ही असाधारण प्रकार के मामलों को छोड़कर, अपीलीय प्राधिकारी कानून में एक कर्तव्य के तहत है कि वह सजा आदेश के खिलाफ पसंद की गई प्रत्येक अपील पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई करे।

13. नियम 851 के खंड (ख) के अधीन, यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक मामले में बर्खास्तगी, हटाने, कमी, पदोन्नति या आवधिक वेतनवृद्धि को रोकने, वेतन की

हानि के साथ निलंबन, किसी विशिष्ट पद से हटाने या उसके अधीन उपबंधित रीति से विशेष परिलब्धियों के आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। खंड (बी) में प्रावधान है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील से निपटने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक अपीलीय प्राधिकारी होगा। इसमें आगे प्रावधान है कि पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेंगे। खंड (ग) में प्रावधान है कि अपीलीय प्राधिकारी के आदेश नियम 853 के तहत प्रावधानों के अधीन अंतिम होंगे, जो स्मारकों और पुनरीक्षण से संबंधित हैं। इसलिए झारखंड पुलिस मैनुअल पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित 15 मई 2006 के सजा आदेश के खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक को अपराधी पुलिस कांस्टेबल को वैधानिक अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करता है - याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार भी है, अगर उसने अपील को प्राथमिकता दी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया।

14. प्रशासनिक प्राधिकारी की ओर से निष्पक्ष रूप से कार्य करने का दायित्व कानून के शासन को सुनिश्चित करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए विकसित किया गया है। यह भी एक सुस्थापित कानून है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने के लिए शक्ति दी जाती है, वहां उस चीज को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं, और प्रदर्शन के अन्य तरीकों को आवश्यक रूप से मना किया जाता है [देखें: *नजीर अहमद बनाम राजा-सम्राट, एआईआर 1936 पीसी 253 (2)]। "नगर निगम" ग्रेटर मुंबई बनाम अभिलाष लाल" (2020) 13 एससीसी 234* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "*नजीर अहमद*" की पुष्टि करते हुए कहा कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकरण में कुछ शक्तियां निहित करता है, तो उक्त प्राधिकरण को केवल उक्त तरीके से इसका प्रयोग करना होता है, अन्यथा नहीं। नियम 853-A प्रदान करता है कि महानिरीक्षक किसी भी मामले में अभिलेख के लिए मांग कर सकता है, भले ही कोई अपील झूठ नहीं है और इस तरह के आदेश पारित कर

सकते हैं के रूप में वह उचित समझ सकता है. खंड (ग) के तहत, महानिरीक्षक नियम 853-ए के तहत किसी भी वैधानिक अपील से निपटते समय जब एक राय बनाता है कि उसे अपील को खारिज करने के बाद सजा को बढ़ाना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन साथ ही वह नियम 853-ए (ए) के तहत शक्तियों के प्रयोग के बारे में उस आदेश में उल्लेख करेगा। इसलिए, नियम 853-ए के खंड (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल दो स्थितियों में किया जा सकता है, अर्थात्, (i) जब सजा के आदेश के लिए कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है और (ii) सजा के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान महानिरीक्षक एक राय बनाता है कि सजा के आदेश को बढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी स्थिति वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होती है और ऐसा होने पर, पुलिस महानिदेशक द्वारा शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से 2023 का 11 एलपीए सं.566 अवैध था। यह अभिलेख का विषय है कि पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 17 नवम्बर, 2008 का आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया गया था जिसके विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील की जाएगी किन्तु दिनांक 17 नवम्बर, 2008 के आदेश की स्वयं पुलिस महानिदेशक ने समीक्षा की है। पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर 2009 के आदेश पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/स्मारक को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश में, पुलिस महानिदेशक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत याचिकाकर्ता को बरी करने के फैसले पर भी ध्यान दिया है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई योग्यता नहीं थी।

15. कभी-कभी उत्प्रेषण की रिट जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को लागू करने में एक वास्तविक कठिनाई उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें कभी संदेह नहीं था कि अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां भी यह पाया जाता है कि अवर न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र के बिना या अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया है। *"नागेंद्र नाथ बोरा और अन्य बनाम हिल्स डिवीजन और अपील, असम और अन्य के आयुक्त"* एआईआर

1958 एससी 398 माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि उत्प्रेषण पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने का एक आधार अभिलेख में स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि है।

16. *"रेजिना बनाम लिवरपूल जस्टिस" में। (एक्स पार्टे डब्ल्यू। (1959) 1 डब्ल्यूएलआर 149* न्यायालय ने किशोर न्यायालय के रूप में बैठे लिवरपूल के न्यायाधीशों द्वारा पारित गोद लेने के आदेश में हस्तक्षेप किया। क्वीन्स बेंच डिवीजन ने माना कि दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1950 की धारा 2 (2) के तहत न्यायाधीशों को केवल विशेष परिस्थितियों में और एक असाधारण उपाय के रूप में आदेश देना चाहिए। आदेश में किसी भी संकेत के अभाव में कि लिवरपूल जस्टिस ने उस उप-धारा के प्रावधानों पर विचार किया था, किशोर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अलग रखा गया था।

17. लॉर्ड पार्कर मुख्य न्यायधीश प्रकार कहा;

> "उन कारणों से, मुझे ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और उत्प्रेषण का आदेश जाना चाहिए। मुझे यह जोड़ना चाहिए कि, निश्चित रूप से, मैंने जो कुछ भी कहा है उसे मामले की योग्यता के लिए किसी भी तरह से जाने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक और आवेदन और सुनवाई पर न्यायमूर्तियों को यह कहने में बहुतायत से उचित होगा कि लेह को बच्चे को गोद लेना चाहिए। दूसरी ओर, वे एक अलग निष्कर्ष पर आ सकते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे किसी भी तरह से इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।

18. झारखंड पुलिस नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अलावा अन्य प्राधिकारी द्वारा अपराधी सरकारी कर्मचारी को केवल कारण बताओ नोटिस जारी करके सजा के आदेश को पलटने की शक्ति की परिकल्पना नहीं की गई है। सजा को बढ़ाने की शक्ति अपीलीय प्राधिकारी में निहित होती है जब दोषी कर्मचारी द्वारा पसंद की गई अपील के साथ जब्त किया जाता है या ऐसे मामलों में जहां कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है। पुलिस महानिदेशक अपीलीय प्राधिकारी नहीं है जो अपील पर विचार कर सकता था यदि अपराधी कर्मचारी ने अपील को प्राथमिकता दी

होती। पुलिस महानिदेशक द्वारा क्षेत्राधिकार में की गई गलती केवल औपचारिक या तकनीकी त्रुटि नहीं है। पुलिस महानिदेशक ने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो कानूनी रूप से उनमें निहित नहीं है

19. यह अच्छी तरह से तय है कि उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी अधिकारिता केवल यह देखने तक सीमित नहीं है कि क्या एक अवर न्यायालय या ट्रिब्यूनल ने अपने मापदंडों के भीतर कार्यवाही की है, इस तरह के अधिकार क्षेत्र को अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। *"सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय" (2003) 6 एससीसी 675* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है -

> "38. इस तरह के मामले अक्सर उच्च न्यायालयों के समक्ष उठते हैं। हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में, यहां तक कि पुनरावृत्ति के जोखिम पर भी सारांशित करते हैं और यहां के रूप में कहते हैं:
>
> (1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में 1-7-2002 से प्रभावी 1999 के अधिनियम 46 द्वारा संशोधन संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है और न ही करता है।
>
> (2) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित वादकालीन आदेश, जिनके विरुद्ध 1999 के सीपीसी संशोधन अधिनियम 46 द्वारा पुनरीक्षण के उपाय को अपवर्जित किया गया है, फिर भी उच्च न्यायालय के उत्प्रेषण और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में चुनौती देने के लिए खुले हैं, और जारी हैं।
>
> (3) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार की घोर त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी किया जाता है अर्थात जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को (i) अधिकारिता के बिना कार्य करते हुए पाया जाता है - अधिकारिता ग्रहण करके जहां कोई मौजूद नहीं है, या (ii) अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक - अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार करके, या (iii) कानून या प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना करते हुए या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में कार्य करते हुए जहां वहां कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है, और इस तरह न्याय की विफलता का अवसर है।

(4) संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता की सीमा के भीतर रखने के लिए किया जाता है। जब एक अधीनस्थ न्यायालय ने एक ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है जो उसके पास नहीं है या वह उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है जो उसके पास है या क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, हालांकि अदालत द्वारा कानून द्वारा अनुमत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है और न्याय की विफलता या गंभीर अन्याय हुआ है, तो उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(5) चाहे वह उत्प्रेषण का रिट हो या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, तथ्य या कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है जब तक कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता है: (i) त्रुटि कार्यवाही के चेहरे पर प्रकट और स्पष्ट है जैसे कि जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना पर आधारित हो, और (ii) इस प्रकार घोर अन्याय या न्याय की घोर विफलता हुई है।

(6) एक पेटेंट त्रुटि एक त्रुटि है जो स्वयं स्पष्ट है अर्थात जिसे किसी भी लंबी या जटिल तर्क या तर्क की लंबी खींची गई प्रक्रिया में शामिल किए बिना माना या प्रदर्शित किया जा सकता है। जहां दो निष्कर्ष यथोचित रूप से संभव हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने एक दृष्टिकोण लेने के लिए चुना है, त्रुटि को सकल या पेटेंट नहीं कहा जा सकता है।

(7) उत्प्रेषण रिट और पर्यवेक्षी अधिकारिता जारी करने की शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना है जहां उच्च न्यायालय का न्यायिक विवेक इसे कार्य करने के लिए निर्देशित करता है कि ऐसा न हो कि न्याय की घोर विफलता या गंभीर अन्याय हो। सावधानी, सावधानी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जब अधीनस्थ न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपर्युक्त दो क्षेत्राधिकारों में से किसी का भी आह्वान किया जाता है और त्रुटि हालांकि सुधार के लिए बुला रही है, फिर भी अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही के समापन पर ठीक किए जाने में सक्षम है और उच्च न्यायालय के उत्प्रेषण या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू करने वाली याचिका पर विचार करना सुचारू रूप से बाधित करेगा या वाद या कार्यवाही का

प्रवाह और/या शीघ्र निपटान। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक महसूस कर सकता है जहां त्रुटि ऐसी है, जैसे, यदि उस क्षण में ठीक नहीं किया जाता है, तो बाद के चरण में सुधार करने में असमर्थ हो सकता है और हस्तक्षेप करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप न्याय का उपहास होगा या जहां इस तरह के इनकार के परिणामस्वरूप लिस का विस्तार होगा।

(8) उत्प्रेषण या पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्वयं को अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं करेगा और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या मूल्यांकन या निष्कर्ष निकालने में त्रुटियों या मात्र औपचारिक या तकनीकी स्वरूप की त्रुटियों को सही करने में लिप्त नहीं होगा।

(9) व्यवहार में, उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए मानदंड और पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग के लिए मांग करने वाले लगभग समान हैं और अंग्रेजी न्यायालयों के विपरीत भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की चौड़ाई ने दोनों न्यायालयों के बीच अंतर को लगभग समाप्त कर दिया है। उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अधिनियम, आदेश या कार्यवाही को रद्द या रद्द कर सकता है, लेकिन उसके स्थान पर अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न केवल उपयुक्त निर्देश दे सकता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय को उस तरीके के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके जिसमें वह उसके बाद या नए सिरे से कार्य करेगा या आगे बढ़ेगा, उच्च न्यायालय उपयुक्त मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अधिक्रमण या प्रतिस्थापन में एक आदेश दे सकता है जैसा कि अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में करना चाहिए था।

20. पुलिस महानिदेशक द्वारा शक्तियों के अवैध प्रयोग के संबंध में, हम मानते हैं कि पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 17 नवंबर 2008 और 23 नवंबर 2009 के आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं।

21. पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका (सेवा) संख्या 6024/2015 में पारित दिनांक 19 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द किया जाता है और 17 नवंबर 2008 के दंड

आदेश को रद्द किया जाता है। परिणाम में, पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 15 मई 2006 के दंड आदेश को बहाल किया जाता है।

22. एलपीए संख्या 566/2023 को पूर्वोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है और, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता रिट याचिका में प्रार्थना के अनुसार परिणामी राहत का हकदार होगा।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया०)

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया०).

पंकज

ए. एफ. आर.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।